

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर

पीठासीन अधिकारी-डॉ०सूरज सिंह नेगी

अपील संख्या 81/2020

तारीख रजू 24.08.2020

1. रामप्रसाद पुत्र बालाराम जाति मीना निवासी गण्डावर तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर
 2. नरेश 3. रामबलवान 4. सत्यनारायण पुत्रान रामप्रसाद जाति मीना निवासी गण्डावर तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर
-अपीलान्ट्स

बनाम

1. रामरतन पुत्र रघुनाथ जाति मीना निवासी गण्डावर तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर
 2. तहसीलदार खण्डार जिला सवाई माधोपुर
-रेस्पोजेन्ट


वकील अपीलान्ट्स-श्री रमेश चन्द गोयल
वकील रेस्पोजेन्ट्स-श्री जगन्नाथ चौधरी

निर्णय दिनांक:-

27.01.2023

अपीलार्थीगण ने यह अपील राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत तहसीलदार खण्डार द्वारा मिसल संख्या 01/2020 मे पारित आदेश दिनांक 29.07.2020 के विरुद्ध प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थीगण के विरुद्ध धारा 183 (बी) आर.टी.एक्ट के तहत खसरा नम्बर 1110/57 रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम गण्डावर से बेदखल करने का आदेश पारित किया गया।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोजेन्ट की तलबी जरिये सम्मन की गई तथा अपीलाधीन निर्णय से संबंधित मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पोजेन्ट की ओर से श्री जगन्नाथ चौधरी एडवोकेट उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन आदेश संबंधी पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस मे कथन किया है कि तहत न्यायालय में रेस्पोजेन्ट द्वारा एक वाद प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी, आरटीएक्ट अपीलान्ट के विरुद्ध पेश किया जिस पर अपीलान्ट की तलबी की जाकर रेस्पोजेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खिलाफ कानून जाकर 183 बी,  पत्र स्वीकार

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

करने के आदेश विधि तरीके से पारित कर दिये गये। यह है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय रूयेदाद मिसल एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं तथ्यों से परे होने से निरस्तनीय है। यह है कि रेस्पोजेन्ट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी राज0टि0एक्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया कि आराजी ख0नं0 1110/57 रकबा 05 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम गण्डावर में स्थित है जिसमें रेस्पोजेन्ट का 1/3 हिस्सा है जिस पर जबरन दिनांक 29.04.2020 को अपीलार्थीगण द्वारा कब्जा कर लिया गया जिसमें नोटिस जारी होना बतलाया लेकिन अपीलार्थीगण को तामील प्रोपर नहीं हुई व एकतरफा कार्यवाही कर निर्णय पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। यह है कि प्रार्थना पत्र में प्रार्थी रेस्पोजेन्टस द्वारा बतलाये गये तथ्य गलत बतलाये है तथा मौके की स्थिति से भिन्न होने से निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। यह है कि अपीलार्थीगण ने कभी भी दिनांक 29.04.2020 को कब्जा नहीं किया बल्कि सत्यता यह है कि रेस्पोजेन्ट ने 2002 में उक्त जमीन 80,000/- रुपये लेकर बेचान गवाहान के समक्ष किया है जिसकी लिखा पढी स्टाम्प 20/- रुपये पर रेस्पोजेन्ट ने अपीलार्थीगण के पक्ष में की है तथा सन् 2002 से लगातार अपीलार्थीगण को कब्जा देने के बाद निरन्तर काश्ता करता आ रहे हैं तथा उक्त जमीन में एक कमरा अपीलार्थीगण ने बना रखा है तथा तार फेन्सिंग कर रखी है जिसकी जांच रिपोर्ट पटवारी हल्का गण्डावर से तलब करने के बाद दिनांक 11.06.2020 को गिरदावर व उपस्थित गवाहान से जांच करने के बाद पेश की है जिसमें कब्जा अपीलार्थीगण का 18 वर्ष से माना है गवाहान व जांच रिपोर्ट पर विश्वास ना कर कानून के विपरित साक्ष के विपरीत निर्णय पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि रेस्पोजेन्ट ने घटना की दिनांक 29.04.2020 गलत साबित होने के बाद भी पारित निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है क्योंकि दिनांक 29.04.2020 को अपीलार्थीगण द्वारा कब्जा ही नहीं किया गया है। अन्त वकील अपीलान्ट द्वारा अपील स्वीकार कर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.07.2020 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

वकील रेस्पोजेन्ट द्वारा वकील अपीलान्ट द्वारा बहस में दिये गये तर्कों का खण्डन करते हुये बहस में तर्क दिया है कि प्रार्थी रेस्पोजेन्ट सं0 1 की संयुक्त खातेदारी कब्जेकाश्त की आराजी खण्डार नम्बर 1110/57 रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम गण्डावर तहसील खण्डार में स्थित है। उक्त आराजी में रेस्पोजेन्ट सं0 1 का 1/6 हिस्सा है लेकिन मौके पर उक्त आराजी का बंटवारा अनुसार रामरतन, जगन्नाथ, गोपीलाल का 1/3, 1/3 हिस्से पर काबिज होकर निरविवाद रूप से काश्त करते चले आ रहे थे तथा प्रार्थी के हिस्से में आई उक्त भूमि पर प्रार्थी ने बैंक ऑफ बडौदा शाखा बहरावण्डा खुर्द से ऋण ले रखा है। उक्त आराजी से अपीलार्थीगण का कोई संबंध व वास्ता नहीं है। यह है कि दिनांक 29.04.2020 को सुबह करीब 8 बजे रेस्पोजेन्ट सं0 1 अपनी खातेदारी की भूमि की सार संभाल करने गया तो वहां पर अपीलान्टस 1 लगा0 4 हाथों में लाठिया लेकर मिले। अपीलान्टस 1 लगा0 4 ने रेस्पोजेन्ट सं0 1 को ऐलानिया धमकी दी कि आज तो तु इस जमीन पर आ गया अगर दुबारा आया तो तेरे

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

इन हाथ पैर तोड़ देंगे तथा रेस्पोजेन्ट सं० 1 की जमीन पर जबरदस्ती लट्ठ के जोर से अतिक्रमण करके कब्जा कर लिया। अपीलान्ट्स द्वारा रेस्पोजेन्ट सं० 1 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1110/57 पर जबरन कब्जा कर रखा है जिसका प्रार्थना पत्र हमारे द्वारा तहसीलदार खण्डार के यहाँ प्रस्तुत करने पर तहसीलदार खण्डार द्वारा हमारे पक्ष में दिनांक 29.07.2020 को आदेश पारित कर उक्त विवादित भूमि से अपीलान्ट्स को बेदखल करने के आदेश पारित किये गये हैं। यह है कि विवादित भूमि पर वर्तमान में हमारी फसल काशत है जिसको अपीलान्ट्स हड़पना चाहते हैं। अंत में वकील रेस्पोजेन्ट्स द्वारा अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.07.2020 को विधि एवं नियमों के अनुसार सही पारित करना बताया जाकर अपील अपीलान्ट्स खारिज कर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश को बहाल रखने बाबत निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा अपीलाधीन निर्णय की मूल पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि रेस्पोजेन्ट रामरतन द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी, आर.टी.एक्ट अदालत मातहत के समक्ष इस आशय का पत्र किया कि आराजी खसरा नम्बर 1110/57 रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा पर अपीलार्थीगण ने दिनांक 29.04.2020 को सुबह करीब 8 बजे रेस्पोजेन्ट सं० 1 को ऐलानिया धमकी देते हुए कि "तुन कहीं पर जाओ हम इस खेत को लेकर रहेंगे तथा आज तो तु इस जमीन पर आ गया अनर दुबारा आया तो तेरे हम हाथ पैर तोड़ देंगे", रेस्पोजेन्ट सं० 1 की जमीन पर जबरदस्ती लट्ठ के जोर से अतिक्रमण करके कब्जा कर लिया, जिसको पुलिस इमदाद द्वारा अपीलान्ट्स को उक्त भूमि से बेदखल कर कब्जा संभलाने बाबत निवेदन करने पर अदालत मातहत द्वारा प्रकरण संख्या 1/2020 दिनांक 04.06.2020 को दर्ज रजिस्टर कर अपीलार्थीगण को नोटिस जारी कर दिनांक 29.07.2020 को रेस्पोजेन्ट रामरतन के पक्ष में निर्णय पारित किया गया। अदालत मातहत द्वारा पटवारी हल्का से मौके की जाँच कराई गयी मुताबिक पर्चा मौका दिनांक 11.06.2020 के द्वारा पटवारी हल्का ने अपनी मौका पर्चा रिपोर्ट में यह अंकित किया कि आराजी ख० नं० 1110/57 रकबा 5.17 बीघा में रामरतन, गोपीलाल, जगन्नाथ पिसरान खुनाथ जाति मीना नि० गण्डावर हिस्सा 1/2 के खातेदार है जबकि मौके पर उक्त खसरा पर मौतविरान पूछने पर बताया कि ख० नं० 1110/57 पर मौखिक बंटवारे अनुसार उक्त ख० नं० पर गोपीलाल, जगन्नाथ व रामरतन के हिस्से में आया है। इस प्रकार रामरतन पुत्र खुनाथ का हिस्सा 1/3 को स्वयं आवेदक ने रामप्रसाद पुत्र बाला जाति मीना को लगभग 15-16 वर्ष पूर्व बेचान करना बताया गया है जबसे ही उक्त हिस्से पर रामप्रसाद पुत्र बाला जाति मीना निवासी गण्डावर ही काबिज चला आ रहा है। अदालत मातहत द्वारा अपने निर्णय दिनांक 29.07.2020 में भी यह माना है कि "प्रकरण का परीक्षण किये जाने पर परिवादी द्वारा बताया गया हाल ही किया गया अतिक्रमण सत्य नहीं पाया गया।" साथ ही पत्रावली का अवलोकन करने पर यह भी पाया जाता है कि अपीलार्थी सं० 1 द्वारा न्यायालय सिविल

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

न्यायालय एवं सिविल मजिस्ट्रेट, खण्डार में दावा अधीन आदेश 7 नियम 1 सी०पी०सी० का एक बंद पत्र पेश किया हुआ है जिसकी वर्तमान स्थिति भी न्यायालय हाजा में अपेक्षित है। अतः अतिरिक्त पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि अपीलार्थीगण संख्या 1 संख्या 4 के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 04.06.2020 को नोटिस जारी किया गया जिसकी पुस्त पर तामील कुलन्दा की रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी सं० 1 की औरत द्वारा अर्जित प्राप्त करना अंकित किया है साथ ही अपीलार्थी सं० 1 के भी हस्ताक्षर अंकित है अर्जित प्राप्त कर्ता औरत सीमा मीना पत्नी रामबलवान अंकित है। ऐसी स्थिति में तामीली अर्जित होने पर भी संदेह पैदा होता है। जिससे प्रस्तुत अपील के बिन्दु संख्या 2 अनुसार अपीलार्थीगण को तामील प्रोपर नहीं होना सही प्रतीत होता है। अदालत मातहत द्वारा बिना पूर्ण निष्कर्ष पर पहुँचे बिना ही एक पक्ष को लाभ पहुँचाने की गरज से उक्त निर्णय अमान्य-मान्य में पारित किया है जो न्याय की श्रेणी में नहीं आता है। अतः मेरी राय में अपील अपीलान्त स्वीकार योग्य पायी जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त स्वीकार की जाती है तथा अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.07.2020 निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार खण्डार को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि पुनः उभय पक्षों को सुना जाकर तथा साक्ष्य सबूत युक्तियुक्त अवसर दिया जाकर नये सिरे से निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 27.01.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ०सूरज सिंह नेगी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर